

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3583/तीन/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.8.2013
- पारित-अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर-प्र. क. 70/09-10 निगरानी

- 1- रामकुमार पुत्र बंदीप्रसाद
 - 2- श्रीमती विमला पत्नि राजकुमार
 - 3- बंदी पुत्र अर्जुन लाल
- तीनों ग्राम कालामढ तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

—आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- जमील खां पुत्र नारंगी मुसलमान
ग्राम कालामढ तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

—अनावेदकगण

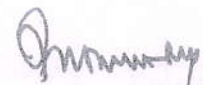
आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी.पी.नायक
अनावेदक क-1 के पेनल लायर श्री डी.के.शुक्ला
अनावेदक 2 के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 9-4-2014 को पारित)

* यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण
क्रमांक 70/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-8-2013 के विरुद्ध
म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण क्रमांक
60/1999-2000 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 से ग्राम कालामढ
स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 571 के मिन रकबा करके रामकुमार पुत्र बंदीप्रसाद को
1.00 है. श्रीमति विमला पत्नि राजकुमार को 0.91 है., बंदीप्रसाद को 1.00 है
भूमि का आवंटन किया, आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जावेगा) क
पट्टा प्रदान कर मौके पर कब्जा दिया गया।



पट्टाग्रहीताओं ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें वादग्रस्त भूमि का पट्टा स्वीकृत है एवं पट्टा प्रदिनांक से पट्टा भूमि पर काविज होकर मौके पर कृषि कर रहे हैं किन्तु पट्टा का अमल शासकीय अभिलेख में छूट गया है इसलिये ग्राम पंचायत प्रस्ताव/ठहराव अनुसार अमल कराया जावे। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी प्रकरण कमांक 41/2008-09 बी 121 पंजीबद्ध किया एवं सुनवाई / उपरांत आदेश दिनांक 27.4.2009 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.12.2000 का अमल खसरे में किये जा आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक कमांक-2 ने अपर आ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। अपर आ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 70/2009-10 निगरानी में आदेश दिनांक 27-8-2013 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के आदेश दिनांक 27.4.2.09 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदकगण एवं अनावेदकगण के अभिभाषकों को बहस में सुन उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तहसील निगरानीकर्ता(अनावेदक क-2)तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 60/99-2000 में एवं अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रकरण कमांक 41/2008-09 बी 121 में हितबद्ध पक्षकार नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 50 - निगरानी का हक - निगरानी को निगरानी का हक प्राप्त नहीं, जो विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा- 50 - दुखी पक्षकार को बताना कि वह आदेश से किस प्रकार दुखी है और उसके हित पर आदेश का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शपथपत्र भी देना होगा।

(Signature)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अनावेदक क्रमांक-2 ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन नहीं दिया है और किस आधार पर वह हितबद्ध पक्षकार है - बताते हुये पक्षकार बनाये जाने का अनुमति आवेदन एवं शपथ पत्र भी नहीं दिया है इसके बाद भी अपर आयुक्त द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करके अंतिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पोहरी द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 32 ए/2009 ई0दी0 (रामकुमार, बट्टीप्रसाद, श्रीमती विमला विरुद्ध जमील शाह एवं ताराचंद) में पारित आदेश दिनांक 31.3.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 4 म0प्र0राज्य कलेक्टर पक्षकार है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण में संलग्न है। माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पोहरी के आदेश दिनांक 31-3-2010 के अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/99-2000 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 के पटटाग्रहीताओं को बैध भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 सहपठित 115,116 - व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिक्री - राजस्व न्यायालय पर बंधनकार है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 - व्यवहार न्यायालय व आदेश/डिक्री - राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से तदाशय व नामान्तरण का अमल शासकीय अभिलेख में किया जावेगा।

किंतु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने उक्त तथ्यों की अनदेखी व है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

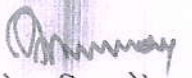
6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वर्ष 2000 से पट प्राप्त उपरांत आवेदकगण ने उखड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाने, मेढों बंधान बनाने में एवं सिंचाई का साधन करने में तथा रखवाली हेतु खेत मकान बना लेने में काफी धन एवं श्रम खर्च किया है आवेदकगण गरीब हैं एवं

[Signature]

बच्चों के जीवनयापन का मात्र यही कृषि भूमि साधन है।

यदि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया जावे, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पट्टा तहसीलदार ने दिनांक 30.12.2000 को दिया है और 30.12.2000 के 13 वर्ष बाद भूमि पुनः शासकीय अभिलेख में शासन की लिखना आवेदकगण की आजीविका को प्रभावित करेगा और इतनी लम्बी अवधि बाद आवेदकगण को प्राप्त पट्टे का अमल शासकीय अभिलेख से हटाना न्यायहित में उचित नहीं माना जावेगा, किन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने इन तथ्यों की अनदेखी की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-8-2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/08-09 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 24-7-09 से आवेदकगण के नाम का शासकीय अभिलेख में किया गया अमल यथावत् रहता है।


(अशोक शिवहरे) -
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर